



परहिर पर सर्वोच्च न्यायालय के दशा-नियम

प्रलिमिस के लिये:

परहिर, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 161, राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894, के हिस्से बनाम भारत संघ (1989), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)।

मेन्स के लिये:

परहिर पर सर्वोच्च न्यायालय के नियम, भारत में परहिर नियम और संबंधित संवैधानिकी और कानूनी प्रावधान।

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने परहिर पर दशा-नियम जारी करते हुए राज्यों को नियम दिया कि प्रतिप्रहिर नीतियों के तहत कैदियों की समय-पूर्व रहिएँ पर विचार करें, और उनके लिये सजा में स्थायी छूट को लेकर आवेदन करना ज़रूरी नहीं है।

- वर्ष 2021 में शुरू किये गए एक स्पष्ट प्रहिर नीति तैयार करनी होगी, जो संवैधानिकी और न्यायिक सदिधांतों के साथ संरेखण सुनिश्चित करें।
- प्रहिर के मानदंड उचित होने चाहिये, जैसा कि 2024 में घोषित किया जाए।
- प्रहिर को मनमाने ढंग से रद्द नहीं किया जा सकता है, यदि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य को कारणों के साथ नोटिस जारी करना होगा और अंतमि नियम से पहले दोषी को जवाब देने की अनुमति दिनी होगी।

प्रहिर नीति पर नवीनतम सर्वोच्च न्यायालय के दशा-नियम (2025):

- राज्यों को दो महीने के भीतर एक स्पष्ट प्रहिर नीति तैयार करनी होगी, जो संवैधानिकी और न्यायिक सदिधांतों के साथ संरेखण सुनिश्चित करें।
- प्रहिर के मानदंड उचित होने चाहिये, जैसा कि 2024 में घोषित किया जाए।
- प्रहिर को मनमाने ढंग से रद्द नहीं किया जा सकता है, यदि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य को कारणों के साथ नोटिस जारी करना होगा और अंतमि नियम से पहले दोषी को जवाब देने की अनुमति दिनी होगी।

नोट:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के वर्ष 2022 के आँकड़ों के अनुसार, भारत की जेलों में 131.4% कैदी हैं, जिनमें 75.8% विवाहित हैं।
- भारत में जेल सांख्यिकी रपोर्ट (2022) के अनुसार, समय से पहले रहिएँ की संख्या 2,321 (2020) से बढ़कर 5,035 (2022) हो गई है।

प्रहिर (Remission) क्या है?

- प्रहिर (Remission) का तात्पर्य सजा की प्रकृति में प्रविरत्न किये बना जेल की सजा की अवधि को कम करना है।
 - इसमें दोषी को न्यायालय द्वारा नियंत्रित मूल अवधि से पहले रहा करने की अनुमति दी जा सकती है, बशरते कि वह विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।
- संवैधानिक प्रावधान:
 - अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को संघीय कानून के तहत या सैन्य न्यायालयों से जुड़े मामलों में अपराध के लिये दोषी ठहराए गए स्थिति की सजा की अवधि कम करने का अधिकार

प्रदान करता है।

- **अनुच्छेद 161** राज्य कानूनों के तहत अपराधों के लिये राज्यपाल को समान शक्तियाँ प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 32 और 226, क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को क्षमा कार्यवाही में शामिल होने के लिये अपने रटि क्षेत्राधिकार का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

- **विधिक प्रावधान:**

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 473 (पूर्व में CrPC की धारा 432): राज्य सरकारों को **प्रदान करता है**, शर्त के साथ या बना शर्त के प्रहिर की शक्ति प्रदान करती है।
- शर्तों का पालन न करने पर प्रहिर को रद्द कथि जा सकता है और बना वारंट के पुनः गरिफतारी हो सकती है।
- BNSS की धारा 475 (पूर्व में CrPC की धारा 433A): मृत्युदंड योग्य अपराधों के लिये आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को 14 वर्ष की कारावास अवधि पूरी करने से पहले रहि नहीं कथि जा सकता।

प्रमुख शब्दावली

- **क्षमा:** अपराधी को पूरणतः सभी संबंधित दंडों और निरिहताओं को समाप्त करते हुए उसकी दोषसदिधि और दंडादेश दोनों को हटा कर उसे दोषमुक्त कथि जाता है।
- **लघूकरण/न्यूनीकरण:** कसी दंड का लघूकरण करना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में परविरति करना।
- **वरिष्ठ:** वशीष परस्थितियों, जैसे कदोषी की शारीरिक दवियागता या ग्रभावस्था को ध्यान में रखते हुए दंड में कमी की जाती है।
- **प्रवलिंबन:** कसी दंड के नष्टिपादन को अस्थायी रूप से वलिबति कथि जाता है, वशीष रूप से मृत्युदंड, जिससे दोषी को क्षमा या दंड में छूट मांगने का समय मिल जाता है।

प्रहिर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के नियम क्या हैं?

- **प्रदान करता है** (2000) में, सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने न्याय और लोक सुरक्षा हेतु एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए प्रहिर अथवा माफी हेतु 5 कारकों को रेखांकित कथि: जसिमें सामाजिक प्रभाव, अपराध की गंभीरता, पुनरावृत्तिका जोखिम, कारावास का आचरण और पुनः एकीकरण की संभावना, शामिल है।
- **प्रदान करता है** (2006) में, सर्वोच्च न्यायालय ने नियम दिया कविविक का प्रयोग न करने, असदभावपूर्वक आशय, बाहरी अथवा अपरासंगकि विचारों पर निभरता, प्रासंगिक सामग्रियों का अपवर्जन, अथवा स्वेच्छाचारिता जैसे आधारों पर प्रदान प्रहिर आदेशों की न्यायिक समीक्षा कथि जाना अनुज्ञयेत है।
- **प्रदान करता है** (2007) में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिषेक कथि, हालाँकि दंड का प्रहिर कसी दोषी का मूल अधिकार नहीं है किंतु राज्य को प्रासंगिक कारकों के आधार पर प्रत्येक मामले पर विचार करते हुए अपनी कार्यकारी शक्ति का विकास रूप से प्रयोग करना चाहयि।
- **प्रदान करता है** (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिरिधारति कथि की CrPC की धारा 432 के तहत प्रहिर कथि जाने हेतु दोषी के आवेदन की आवश्यकता होती है और सरकार दवारा **प्रदान करता है** स्वीकार नहीं कथि जा सकता है।
- **प्रदान करता है** (2013) में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कन्यायालयों के पास स्वयं से प्रहिर करने का अधिकार नहीं है, तथा इस तथ्य पर बल दिया कप्रहिर की प्रक्रिया औपचारिक अनुरोध के माध्यम से शुरू की जानी चाहयि।
- **प्रदान करता है** (2015) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी के "अंतमि क्षण" तक बना कसी प्रहिर के आजीवन कारावास को बरकरार रखा और इसे मृत्युदंड का विकल्प माना।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2024 में **प्रदान करता है** में 11 दोषियों के लिये **गुजरात सरकार के प्रहिर आदेश** को रद्द कर दिया और वर्ष 2022 के नियम को अपास्त कथि, जसिके अंतर्गत गुजरात को उनकी समयपूर्व रहिई पर नियम करने की अनुमतिप्रदान की गई थी।
 - न्यायालय ने नियम सुनाया की CrPC की धारा 432(7) के अनुसार, प्रहिर के लिये "समुचित सरकार" वह है जहाँ अपराधी को दण्डादेश कथि गया है, न कि जहाँ अपराध कारति कथि गया। इस सदिधांत की पुष्टि **प्रदान करता है** (2015) से की गई।
- **प्रदान करता है** (2024) में, सर्वोच्च न्यायालय ने नियम दिया कप्रहिर की स्थितियों युक्तियुक्त होनी चाहयि, यह सुनिश्चित करते हुए कथि न तो मनमाना रूप से कठोर हों और न ही अस्पष्ट हों।

और पढ़ें:

- **क्षमादान शक्ति के विभिन्न प्रकार क्या हैं?**
- **प्रहिर करने संबंधी कौन-से मुद्दे हैं?**

Q. भारतीय कानून के तहत क्षमा, दंड में परविरतन, छूट, प्रशमन और राहत के बीच अंतर बताइए। ये कार्यकारी शक्तियाँ न्याय और सुधार के सदिधांतों में किसि प्रकार योगदान देती हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगित वर्ष के प्रश्न

?????:

प्रश्न. मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के विलिंब के उदाहरण न्याय प्राख्यान (डनियल) के रूप में लोक वाद-विवाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिये एक समय-सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहये? विश्लेषण कीजिये। (2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/scs-direction-on-remission>

